Tasleema
14/08/2026

~~भारत-बांग्लादेश रिश्ते में तस्लीमा~~

(1) (A)

भारत-बांग्लादेश रिश्ते में तस्लीमा-हसीना फैक्टर

बांग्लादेश से निर्वासित विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थन में कोलकाता में बोलीं और इसके तुरंत बाद हसीना ने कहा — 'मैं बांग्लादेश लौटूंगी, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े।' कट्टरपंथी मुस्लिम, इस्लाम कोड के खिलाफ बेधड़क खरी-खरी लिखने, बोलने के कारण विवादों से घिरी तस्लीमा नसरीन अपने स्वदेश मुल्क बांग्लादेश से तीन दशकों से निर्वासित/निष्कासित हैं। इसी वजह से उन्हें 2007 में वाममोर्चा शासनकाल में कोलकाता छोड़ना पड़ा, जबकि वे सुरक्षित यहां रहना चाहती थीं। 19 साल बाद तस्लीमा उस समय कोलकाता लौटीं, जब पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। 02 अगस्त को एक कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता पहुंचीं तस्लीमा नसरीन का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बांग्लादेश के घटनाक्रम से करते हुए कहा कि शेख हसीना की वापसी पर अनिश्चितता चिंता की बात है। तस्लीमा ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध का विरोध किया और कहा कि राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लोकतंत्र के खिलाफ कदम है। इसके तीन दिन बाद 05 अगस्त को दिल्ली स्थित विदेशी संवाददाता क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि मैं दिसंबर में अपने मुल्क लौटूंगी। हसीना ने कहा कि चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं बांग्लादेश लौटूंगी।

शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के खिलाफ जुलाई-अगस्त 2024 [redacted] बांग्लादेश में हुए उग्र छात्र आंदोलन पर काबू पाने में विफल होने के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद [redacted] के साथ-साथ देश भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद से वे भारत में रह रही हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा छात्र नेताओं के दबाव में गठित अंतरिम सरकार के सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता [redacted] मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, एक विशेष अध्यादेश के तहत बने नये कानून के अंतर्गत अवामी लीग को आतंकी गुट घोषित कर दिया गया। शेख हसीना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोधियों की कथित हत्या समेत कई गंभीर अपराधों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए और उन्हें सजा-ए-मौत सुनायी गयी। भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में [redacted] तल्खी आ गयी। शेख हसीना को [illegible] के लिए सौंपे जाने के बांग्ला सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। [redacted] शेख हसीना ने शायद खुद के या भारत सरकार [redacted] की सलाह से चुप्पी साध रखी थी। [redacted] तस्लीमा नसरीन के बयान इस मुद्दे पर खुलकर बोलने के बाद शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी। दोनों [redacted] भारत [redacted] बांग्लादेश के महिलाओं के खुलकर बोलने के बाद [illegible] का चिंतन-मनन और शेख हसीना के नए प्रत्यर्पण समेत विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत का [redacted] सिलसिला शुरू हुआ। [redacted] ढाका के लिए हसीना की वापसी अहम है।

तसलीमा नसरीन के भारत प्रवास के दौरान बुद्ध भी लिखने बोलने का असर दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते के अलावे भारत के अंदरूनी सियासी राजनीति पर भी पड़ा है। अभी उसमें नया मोड़ आ गया है। क्योंकि तसलीमा जब कोलकाता में रहने आयी थीं उस समय वहाँ अधिकतर राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थीं। अभी जब तसलीमा को भारत में रहते भी रहने की दूर है, उस समय अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल की नयी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तसलीमा का स्वागत किया। अब तसलीमा को तय करना है कि वो अब वापस कोलकाता आकर रहती हैं या नहीं। 2002 में जब तसलीमा कोलकाता में रहने आयी थीं, उस समय भी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा गठजोड़ सरकार थी। नवंबर 2007 में पश्चिम बंगाल के वाममोर्चा मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले तसलीमा को कोलकाता छोड़ने कहा।

परिवारवाद तसलीमा ने अभी अगस्त 2026 में कोलकाता में करम रखा है। शेख हसीना के समर्थन में बोलने का इस समय भारत में है, भारत सरकार का हसीना के प्रति हमदर्दी। हसीना के भी शासनकाल में तसलीमा को बांग्लादेश आने की इजाजत नहीं थी। 1994 में जब तसलीमा को बांग्लादेश से कठमुल्लाओं के फतवे के कारण निर्वासित किया गया था, उस समय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सत्ता में थी और बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं।

खालिदा जिया शासन के दौरान भारत-बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं थे। थोड़े दिनों बाद शेख हसीना की नेतृत्व अवामी लीग सत्ता में आयी और शेख हसीना लगातार प्रधानमंत्री बनी रहीं। शेख हसीना ने न तो मुल्ला-मौलवियों के दबाव में कोई काम किया और न ही उनसे भयभीत होती थीं। उसमें भारत से बेहतर रिश्ते बनाने के साथ-साथ तस्लीमा को बांग्लादेश न आने देना भी शामिल रहा।

वैसे तो तस्लीमा का सारा लेखन ही विवादित लेकिन उनकी किताब 'द्विखंडिता' और सात खंडों में छपी (आपबीती) मुस्लिम 'निर्वासन' को लेकर ज्यादा बवाल मचा है। तस्लीमा ने हमेशा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और हरम मानसिकता वाले मुल्लाओं के कट्टरपंथ तथा तीन बार तलाक बोलने जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठायी है। (तस्लीमा इस्लामपंथ के खिलाफ जितना मुखर बोलती आयी हैं, उतना ही कॉमन सिविल कोड के समर्थन में बोल रही हैं। उनकी किताबों का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और तस्लीमा यूरोपीय देशों में रह चुकी हैं। उनके पास अभी भी स्वीडन का वीजा है। (कोलकाता को अपना 'दूसरा घर' मानने वाली तस्लीमा कोलकाता के जरिए राजनीतिक / मजहबी विवाद के इर्द-गिर्द रही हैं। अभी अगस्त में तस्लीमा कोलकाता में कट्टरपंथ विरोधी भाजपा समर्थित [illegible] कार्यक्रम में भाग लेने आयीं जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी थे। तस्लीमा ने कार्यक्रम को जोरदार शब्दों में समान नागरिक संहिता (यू सी सी) का समर्थन किया और कहा कि भेदभाव खासकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभाव खत्म करने के लिए ऐसा कानून जरूरी है

तस्लीमा ने कहा कि भारत में यूसीसी लागू हो और बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में भी ऐसा कानून बने। उन्होंने कहा- मैं विगत 40 सालों से यूसीसी जैसे कानून के लिए लड़ रही हूं।

तस्लीमा ने ऐसे समय में यूसीसी की वकालत [illegible] की है, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 2026 उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है। भाजपा शासित असम, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र सरकारों द्वारा यूसीसी कानून बनाने के [illegible] अभियान, इसलिए कुछ राज्यों में रोक को कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

उधर बांग्लादेश में शेख हसीना के अपदस्थ होने और निर्वासन के बाद से हिन्दू अल्पसंख्यकों [illegible] पर हमले तेज हो गए। हिन्दुओं के विवाह स्थलों, आगजनी [illegible] की वारदातें बढ़ गयीं। भारत के बार-बार के ऐतराज जताने के बावजूद बंद नहीं हुए। 2025 संसदीय चुनाव में छात्र संगठनों के समर्थन से [illegible] बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, भारी बहुमत से सत्ता में आयी। जिस पर शेख हसीना ने प्रतिबंध लगाया था। 2024 आंदोलन के दौरान बेगम खालिदा का लंबी बीमारी के कारण इंतकाल हो गया। कई वर्षों से लंदन में निर्वासन में रह रहे खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। लेकिन भारत से उनके रिश्ते में तल्खी बरकरार है और हिन्दुओं पर हमले भी बंद नहीं हुए।

तस्लीमा ने बोलबाला कार्यक्रम में भारत-बांग्लादेश अच्छे रिश्ते की उम्मीद जताते हुए कहा कि भारत सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करती है।

इसके साथ-साथ तस्लीमा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉकयेन जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन और बांग्लादेश में 2024 में भी छात्र आंदोलन को समर्थन दिया था। तस्लीमा ने इस छात्र आंदोलन के समर्थन किया, जिसने अवामी लीग सरकार को सत्ता से बाहर किया।

तस्लीमा [illegible] ने खुले तौर वर्तमान और अतीत को याद करते हुए भावुक होकर युद्ध इस बांग्लादेश में [illegible] ने सरकार ने [illegible] आने को मजबूर किया, [illegible] दूसरी ओर नहीं किया और दूसरी ने [illegible] स्वागत किया।

गौरतलब है कि मई, 2025 में जब बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार शेख हसीना और अवामी लीग का अंग का राजनीतिक दस्तक बिल्कुल बंद करने [illegible] की घोषणा की, उस समय भी भारत सरकार ने तस्लीमा प्रेम दिखाया। [illegible] तस्लीमा को पूरे देश के साथ-साथ कोलकाता में भी घूमने-टहलने की आजादी।

[illegible] तस्लीमा और शेख हसीना के बांग्लादेश के विषय में कुछ खुलके से कुछ ही दिन पहले [illegible] राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद (जातीय संसद) के स्पीकर शमीमुद्दीन बांग्लादेश की संसद इस्तीफा पत्र को राष्ट्रपति के पास हमारे भेजे गए इस्तीफा पत्र को राष्ट्रपति ने उनकी अपनी बिगड़ती सेहत का हवाला दिया, मगर [illegible] इसके पीछे राजनीतिक उलझन में इसका कारण सियासी मतभेद को [illegible] राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का 5 साल का कार्यकाल अप्रैल, 2028 में समाप्त होनेवाला था।

लेकिन अल्लाहक़ बीएनपी और अवामी लीग की 7

• जैसी ही प्रतिद्वंद्वी विपक्षी जमायत-ए-इस्लामी नेताओं को अवामी लीग शासनकाल के राष्ट्रपति भवन नहीं था। जैसा अंग्रेजी अखबार का कहना है कि ए-डी-आरोपण से हुए सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ सभी सीटें पर खाली कराए गए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्मान अभी बने हुए थे। 13 अगस्त को बीएनपी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को उम्मीदवार और 20 अगस्त को चुनाव का प्रस्ताव दिया। शेख हसीना के स्वदेश लौटने की बात मीडिया के जरिए प्रचारित होने के पांचवें दिन 10 अगस्त को ढाका में भारतीय उच्चायुक्त रिनेथ सिवेरी प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मिले। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) प्रमुख पराग जैन ने भी ढाका में जमात के सलाहकार ए-ए के एम-शम्सुल इस्लाम से मुलाकात की। बांग्लादेश सरकार ने भारत को भरोसा दिलाया कि शेख हसीना को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, मगर उन्हें अदालती प्रक्रिया का सामना करना होगा। शेख हसीना ने अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कहा — मैं मानती हूं कि ढाका लौटने पर गिरफ्तार किया जा सकता है, भले हत्या भी हो सकती है, फिर भी मैं लौटूंगी। भारत ने बांग्लादेश के इस आरोप को खारिज किया कि हसीना की प्रेस कान्फ्रेंस भारत-आयोजित थी।

8

इसी समय बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया गया। 12 और 13 सितंबर को भारत बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी, जिसमें शामिल होने के लिए तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। इस व्यापारिक संगठन का बांग्लादेश भी सदस्य है।

इस प्रसंग के शुरू और उतार-चढ़ाव देखने के लिए जरा पीछे चलते हैं। भारत में रहते हुए तसलीमा पहले बोल चुकी हैं — 'मैं वोट बैंक की राजनीति का शिकार हूं, सुरक्षा की जिंदगी जी रही हूं। मैं यहां राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनना चाहती।' लेकिन रहीं भारत में ही।

2007 में कोलकाता से निर्वासित किए जाने के बाद भाजपा और आर एस एस के लोगों में तसलीमा को अपने पक्ष में करने की होड़ मच गयी। सबसे आगे बढ़कर न्योता उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा था। एस एस प्रमुख के. एस. सुदर्शन ने अपने घर बुलाया था। उसके बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलावा भेजा। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तसलीमा को दिल्ली के बाहरी इलाके में अज्ञात स्थान पर रखा और मुंह बंद रखने कहा।

2012 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुस्तक मेला में तसलीमा को 'निर्वासन' पुस्तक के विमोचन के लिए आने की इजाजत नहीं दी। बांग्लादेशी तबलीगी और अपने यहां के मुस्लिम कट्टरपंथियों का दबाव था।

0 ——→ 2017 में केंद्र में भाजपा गठजोड़
सत्ता में थी और राजस्थान में भी भाजपा सरकार थी
कांग्रेस जयपुर साहित्य उत्सव में तस्लीमा को बुलाने के जबरदस्त
विरोध के कारण उन्हें जयपुर से भगाया गया और
आयोजकों को कहना पड़ा कि आगे से तस्लीमा
को नहीं बुलाया जाएगा। तस्लीमा ने उस समय भी
समान नागरिक संहिता की वकालत करने के साथ-साथ
मुसलमानों के रोहिंग्या लोगों की नागरिकता दे डाली।
इतना जहर उगलने के बावजूद
तस्लीमा को शरणार्थी का दर्जा नहीं है और
कांग्रेस शासनकाल की तरह आज भी
वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए भाजपा गठजोड़
सरकार की दया पर टिकी है। भाजपा नेताओं से
तस्लीमा के लिए 'अतिथि देवो भव' परंपरा का पालन
करने के अलावा बांग्लादेश से रिश्ते बेहतर रखने और
बेबस लेखिका की सलामती भी टिकी है।